

विधि (प्रश्न-पत्र-I)

निर्धारित समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 250

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

(उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़िए)

इसमें आठ प्रश्न हैं, जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द-सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

LAW (PAPER-I)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड—A / SECTION—A

1. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

10×5=50

- (a) “भारत में ‘प्रसाद के सिद्धान्त’ का पूर्णतः अनिर्बंधित उपयोग अस्तित्व में नहीं है।” सेवा विधिशास्त्र के सम्बन्ध में विशदीकरण कीजिए।

“The ‘Doctrine of Pleasure’ in its absolute unrestricted application does not exist in India.” Elucidate with regard to service jurisprudence.

- (b) “यदि विधायन और प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को निराकृत अथवा अपहृत कर (हटा) दिया जाए, तो संविधान जैसा है, वैसा ही समाप्त हो जाएगा।” आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

“If the power of judicial review of legislation and administrative actions is abrogated or taken away, the Constitution will cease to be what it is.” Critically evaluate.

- (c) विधायी प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? संविधान के अन्तर्गत ऐसे किसी राज्यक्षेत्र, जो किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, के लिए किसी भी सूची में, किसी भी विषय पर, विधि-निर्माण किए जाने हेतु संसद को सशक्त किया गया है। व्याख्या कीजिए।

What do you understand by legislative process? Under the Constitution, the Parliament has been empowered to make law on any matter, in any list, for any territory not included in a State. Explain.

- (d) ‘निदेशक तत्त्वों’ में प्रयुक्त शब्द ‘राज्य’ का वही अर्थ है जैसा कि अनुच्छेद 12 द्वारा मूलभूत अधिकारों के प्रवर्तन के उद्देश्यों हेतु दिया गया है। यदि कोई अपवाद हो, तो उसके प्रकाश में परीक्षण कीजिए।

The word ‘State’ used in the ‘Directive Principles’ has the same meaning as has been given to it by Article 12, for the purposes of enforcement of the Fundamental Rights. Examine in the light of exceptions, if any.

- (e) भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। व्याख्या कीजिए। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विवाद हो जाता है, तब उसका निपटारा कौन करेगा? विवेचना कीजिए।

The President in India is elected not directly by the people, but by the method of indirect election. Explain. Who will decide in case any dispute arises in connection with the election of the President? Discuss.

2. (a) “संविधान के अनुच्छेद 21 का निर्वचन करते समय उच्चतम न्यायालय ने ‘विधि की सम्यक् प्रक्रिया’ की अवधारणा को अप्रत्यक्ष (परोक्ष) रूप से भारतीय संविधान में प्रविष्ट किया है, जिसके कारण इसकी परिधि का अत्यन्त ही विस्तार हो गया।” निदर्शक (प्रमुख) वाद-विधियों की सहायता से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए।

“While interpreting Article 21 of the Constitution, the Supreme Court introduced the concept of ‘due process of law’ indirectly into the Constitution of India, and thereby expanded its scope considerably.” Support your answer with the help of leading case laws.

20

- (b) “‘संविधानवाद’ का मूल रूप में अर्थ होता है—‘परिसीमित सरकार’ अथवा ‘सरकार पर परिसीमा’। यह मनमानी करने की शक्तियों की प्रतिस्थापना (ऐन्टीथीसिस) है।” विवेचना कीजिए।

“‘Constitutionalism’ connotes in essence—‘limited government’ or ‘a limitation on government’. It is the antithesis of arbitrary powers.” Discuss.

15

- (c) “विधायिका को प्रत्यायोजित अधिनियम में ही आवश्यक नीति अथवा नीतिगत मानकों का निरूपण कर देना चाहिए, तत्पश्चात् प्रत्यायुक्त (प्रतिनिधि) विधायी नीति के अग्रसारण में विधि-निर्माण करेगा।” सुसंगत वाद-विधियों की सहायता से उक्त कथन की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।

“The Legislature itself must set the essential policy, or lay down standards or policy in the Delegating Act and the delegate would then legislate to advance the legislative policy.” Elaborate the statement with the help of relevant case laws.

15

3. (a) केशवानन्द, न्यायिक सृजनात्मकता तथा नीति-निर्माण में उच्चतम न्यायालय की उच्च-स्तरीय भूमिका का दृष्टान्त है और इसे गोलकनाथ के विनिश्चय में सुधार के रूप में देखा जा सकता है। सुसंगत तर्कों की सहायता से परीक्षण कीजिए।

Keshavananda illustrates judicial creativity and the policy-making role of the Supreme Court of a very high order and could be regarded to be an improvement over the formulation in Golaknath. Examine with the help of relevant arguments.

20

- (b) ‘सांविधानिक शासन’ एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सरकार का प्राधिकार सीमित, परिभाषित तथा एक सर्वोच्च लिखित अथवा अलिखित संविधान द्वारा रचित है। भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची के विशेष सन्दर्भ में विश्लेषण कीजिए।

‘Constitutional governance’ is a system where government authority is limited, defined and structured by a supreme written or unwritten constitution. Analyze with special reference to the Sixth Schedule of the Indian Constitution.

15

- (c) “‘प्राकृतिक न्याय’ की अवधारणा भिन्नता की विषय-वस्तुओं की है तथा यह अलग-अलग मामलों में विभिन्न प्रक्रियात्मक मानक आरोपित करती है।” व्याख्या कीजिए।

“The concept of ‘natural justice’ is of variable content and imposes variable procedural norms from case to case.” Explain. 15

4. (a) “भारत का उच्चतम न्यायालय एक बहु-अधिकारिता का न्यायालय है तथा इसे विश्व का सर्वशक्तिशाली शीर्ष न्यायालय कहा जा सकेगा।” उक्त कथन की सुसंगत संवैधानिक उपबन्धों की सहायता से न्यायसंगत पुष्टि कीजिए।

“The Supreme Court of India is a multi-jurisdictional Court and may be regarded as the most powerful Apex Court in the world.” Justify this statement supported by relevant constitutional provisions. 20

- (b) “भारत में आपातकाल की उद्घोषणा के लिए वांछित सन्तुष्टि राष्ट्रपति की होनी चाहिए, न कि केन्द्रीय कैबिनेट की।” क्या आप इस बात से सहमत हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा उद्घोषणा के प्रभावों की भी विवेचना कीजिए।

“It is the satisfaction of the President and not of the Central Cabinet, for proclamation of emergency in India.” Do you agree with it? Critically examine and also, discuss about the consequences of such proclamation. 15

- (c) “‘ऑम्बड्समैन’ विधायी कार्य से उत्पन्न, प्रशासन पर पर्यवेक्षण की व्यवस्था है।” उक्त कथन का भारत के परिप्रेक्ष्य में उदाहरणों की सहायता से विशदीकरण कीजिए।

“An ‘Ombudsman’ is the projection of the legislative function of supervising the administration.” Elucidate this statement in Indian perspectives with the help of examples. 15

खण्ड—B / SECTION—B

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

10×5=50

- (a) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि, ‘विधि’ शब्द के सही अर्थों में विधि है, अथवा नहीं? परीक्षण कीजिए।

Whether International Law is a law in the true sense of the term ‘law’ or not? Examine.

- (b) उन सिद्धान्तों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा देशज (राष्ट्रीय) विधि के मध्य सम्बन्ध की व्याख्या हेतु प्रतिपादित किया गया है।

Critically examine the theories which have been propounded to explain the relationship between International Law and Municipal Law.

- (c) 'आश्रय (शरण)' क्या है? क्या किसी व्यक्ति को किसी अन्य देश में 'शरण का अधिकार', अभियोजन से बचने के लिए मौलिक अधिकार है? व्याख्या कीजिए।

What is 'asylum'? Is 'Right to Asylum' a fundamental right of a person in other country to save from prosecution? Explain.

- (d) संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य द्वारा 'दोहरा वीटो' लगाए जाने से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर इसके प्रभाव की विवेचना भी कीजिए।

What do you mean by imposing 'Double Veto' by a permanent member of the Security Council of the United Nations? Also, discuss its impact on decision-making process of the United Nations.

- (e) 'राज्य उत्तराधिकार' तथा 'राज्य मान्यता' से आप क्या समझते हैं? दोनों के मध्य अन्तर स्थापित कीजिए।

What do you understand by 'State succession' and 'State recognition'? Differentiate between them.

6. (a) "वर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था, मुक्त बाजार की ताकतों के प्रभाव में दिशा-निर्देशित एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा द्वारा चालित है। यह वस्तुओं तथा सेवाओं, जिसमें तकनीकी भी सम्मिलित है, के मुक्त आवागमन पर आधारित है।" इस सन्दर्भ में टैरिफ तथा व्यापार के सामान्य समझौता (GATT) के अन्तर्गत गैर-भेदभाव और मुक्त व्यापार के सिद्धान्तों की भूमिका की विवेचना कीजिए।

"The present world economic order is supposed to be guided by the operation of free market forces propelled by free competition, based on free movement of goods and services including technology." Discuss the role of the principle of non-discrimination and free trade under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in this regard.

20

- (b) 'हस्तक्षेप' के आधारों तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, जिनके अन्तर्गत आत्म-प्रतिरक्षा के लिए विधि-सम्मत रूप से बल प्रयोग किया जा सकेगा। इसकी परिसीमाएँ भी दीजिए।

Discuss the grounds of 'intervention' and its types. State the circumstances under which lawful recourse to use of force for self-defence could be taken. Give its limitations also.

15

- (c) “अन्तर्राष्ट्रीय विधि को उस विधि के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो प्रमुखतः उन सिद्धान्तों तथा आचरण के नियमों पर आधारित होता है, जिन्हें राज्य स्वयं को अनुपालन करने के लिए बाध्य मानते हैं और इसी कारण वे अपने पारस्परिक सम्बन्धों में सामान्यतया उनका अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।” व्याख्या कीजिए।

“International Law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which States feel themselves bound to observe and, therefore, do commonly observe in their relation to each other.” Explain.

15

7. (a) राज्यक्षेत्रीय समुद्र तथा संलग्न क्षेत्र के सन्दर्भ में ‘कोर्फू चैनल प्रकरण’ में आए तथ्यों तथा समुद्र विधि के सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए। वर्तमान होरमुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होरमुज़) समस्या के सन्दर्भ में अपना अभिमत दीजिए कि किस हद तक विदेशी जहाजों की ‘निर्दोष यात्रा’ के सिद्धान्त के प्रकाश में समुद्र विधि के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (1982) के अन्तर्गत, उक्त समस्या का निराकरण किया जा सकता है। समझाइए।

Discuss the facts and the Principles of the Law of the Sea, emerged in ‘Corfu Channel Case’, with reference to the territorial sea and contiguous zone. Give your opinion, how far the ‘Strait of Hormuz’ problem could be resolved under the UN Convention on the Law of the Sea (1982) in the light of the principle of ‘innocent passage’ by foreign vessels. Explain.

20

- (b) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के गठन, शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए।

Discuss the composition, powers and functions of the Security Council of the United Nations for the maintenance of international peace and security.

15

- (c) ‘राष्ट्रीयता’ पद को परिभाषित कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीयता अर्जित किए जाने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। ‘राष्ट्रीयता’ तथा ‘अधिवास’ में अन्तर बताइए।

Define the term ‘nationality’. State the various modes of acquisition of nationality by a person. Differentiate between ‘nationality’ and ‘domicile’.

15

8. (a) “ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, 1944 द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग और आर्थिक विकास के लिए, नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा दिए जाने हेतु, दो संस्थाओं के परिनियमों को अपनाया गया।” उपर्युक्त कथन की अन्तर्राष्ट्रीय मंच के सम्बन्ध में विवेचना कीजिए।

“The Bretton Woods Conference, 1944 adopted the statutes of two institutions to promote New International Economic Order for international financial cooperation and economic development.”

Discuss the above statement in terms of the International Forum.

20

- (b) मानव पर्यावरण के संरक्षण तथा बेहतरी के लिए वैश्विक उष्णता (ग्लोबल वार्मिंग) के क्योटो पर्यावरण समिट, 1997 के 'पूर्व तथा पश्चात्वर्ती' विकास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

Discuss briefly 'pre and post' developments of Kyoto Environment Summit on Global Warming, 1997 for the protection and improvement of the human environment.

15

- (c) मानवाधिकारों से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों के प्रवर्तन हेतु, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत, निर्धारित प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।

What do you mean by Human Rights? Discuss the procedure for the enforcement of Human Rights of a person as laid down under the International Law.

15

★ ★ ★